

अरित की राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड ा

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पां. 68] No. 681

नर्ह दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2006/चैत्र 17, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2006/CHAITRA 17, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुरुक महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2006

(निर्णायक समीक्षा)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जिंक आक्साइड के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/4/2005-डी जी ए डी. - जबिक 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिन्हें एतद्पश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए दिनांक 5 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. 62/1/2000-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. (जिसे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित "जिंक आक्साइड" (जिसे एतद्पश्चात संबद वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शूल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, जिसे सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 40/2001-सीमाशुल्क दिनांक 9 अप्रैल, 2001 द्वारा लागू किया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 2001 को अधिसूचना सं. 62/1/2000-डीजीएडी के तहत अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे और दिनांक 2 नवम्बर, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 115/2001-सीमाशूल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

समीक्षा हेतु अनुरोध 2.

जबिक सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे हटाया न जाए तो लागू किए जाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है।

और जबिक संबंधित नियमावली में प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने की अपेक्षा की गई है और यदि वे प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हों कि ' ऐसे शुल्क को लागू रखने का पर्याप्त औचित्य है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार इसकी समयावधि का विस्तार करने की सिफारिश कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, भारतीय उत्पादक एसोसिएशन विधिवत रूप से तथ्यपूर्ण याचिका के साथ प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जिसमें समीक्षा एवं पाटनरोधी शुल्क लागू रखने का अनुरोध किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रक्रिया ऐसे शुल्क के समय विस्तार की आवश्यकता की जाँच करने के लिए उपयुक्त होगी।

समीक्ष का आधार

लागू पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करने और उसको बढ़ाने का अनुरोध किया गया है । यह अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि वर्तमान शुल्क के वापस ले लिए जाने के परिणामस्वरूप पाटन को जारी रहने और उसका पुनरावृति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना बन सकती है ।

जांच की शुरूआत

समीक्षा की आवश्यकता को साबित करते हुए घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्यों को आधार पर संतुष्ट होते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के अधिनियम की धारा 9(क) 5 और नियम 23 के अनुसार, 5 अक्तूबर, 2001 को अधिसूचित आंतेम जांचपरिणाम में सिफारिश किए गए पटनरोधी शुल्क और दिनांक 2 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 115/2001-सीमाशुल्क द्वारा लागू निश्चयात्मक शुल्क के विस्तार की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा का आरंभ करते हैं।

5 विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची -। के सीमाशुल्क शीर्ष 2817 अथवा 3812.30 के तहत वर्गीकृत जिंक ऑक्साइड है ।

6 शामिल देश

वर्तमान जांचों में शामिल देश चीन जन गण. है (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा जाएगा) ।

प्रक्रिया

जांच से यह निर्धारित हो सकेगा कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षिति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का लगातार जारी रखा जाना आवश्यक है और यदि शुल्क को हटाया या उसमें परिवर्तन किया जाता है, अथवा दोनों को अमल में लाया जाता है तो क्या क्षिति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

(ii) समीक्षा में दिनांक 5 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 62/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा ।

8. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक (12 महीने) की है।

9. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों और उपयोक्ताओं तथा भारतीय उत्पादकों को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से

निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (ढीजीएडी), कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से नीचे दी गई समयाविध के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

10. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के लिए कोई भी अनुरोध लिखित रूप में दिया जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के मीतर पहुँच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के मीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हो या प्राप्त सूचना अपूर्ण हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

11. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाघा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2006 (Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Zinc Oxide originating in or exported from China PR.

No. 15/4/2005-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of "Zinc Oxide" (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (referred to as subject country) vide Notification No. 62/1/2000-DGAD dated 5th March, 2001, which were imposed vide Customs Notification No. 40/2001-Customs, dated the 9th April, 2001. The Designated Authority came out with final findings on 5th October 2001 vide notification no 62/1/2000-DGAD and the definitive anti dumping duty was imposed vide Customs Notification No. 115/2001-Customs dated 2nd November, 2001.

2. Request for Review

WHIEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

AND WHEREAS the Rules supra require the Authority to review the need for extension of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received that there is sufficient justification for extension of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its extension.

In terms of the above provisions, Association of Indian Producers has approached the Authority with a duly substantiated petition requesting for a review and extension of anti-dumping duties. The Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for extension of such duty.

3. Grounds for review

The request is for extension and enhancement of the anti-dumping duties in force. The request is based on the grounds that revocation of the present duty is likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

4. Initiation

Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted on behalf of the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a

review in accordance with Section 9(A)5 of the Act and Rule 23 of Rules, to review the need for extension of anti-dumping duties recommended vide final findings notified on 5th October 2001 and definitive duty imposed by Notification No. 115/2001-Customs dated 2nd November, 2001.

5. Product under Consideration

The product under consideration in the present investigation is Zinc Oxide classified under custom sub-heading 2817 or 3812.30 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

6. Countries Involved:

The country involved in the present investigations is China PR (referred to as subject country hereinafter).

7. Procedure

- (i) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.
- (ii) The review will cover all aspects of Notification No 62/1/2000-DGAD dated 5th October 2001

8. Period of Investigation

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st January 2005 to 31st December 2005 (12 months).

9. Submission of Information

The exporters in subject country, their government through their Embassy/High Commission in India, the importers and users in India known to be concerned and the Indian Producers are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

11. Inspection of Public File

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority